कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

अमेरिका-ईरान तनाव से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते टकराव से सप्लाई बाधित

नई दिल्ली, 13 अप्रैल वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया और यह एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, वार्ता के विफल होने और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न गंभीर अनिश्चितता के कारण देखी गई है. ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत करीब 7.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 102.80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि पश्चिम टेक्सास मध्यवर्ती कच्चा तेल 8.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 104.88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा. दोनों बेंचमार्क में यह उछाल दर्शाता है कि वैश्विक निवेशक कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और बाजार में जोखिम प्रीमियम तेजी से बढ़ गया है.

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हालिया वार्ता का विफल होना है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक गहरा गया है. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब रिपोर्ट्स में यह संकेत मिला कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी या सख्त नियंत्रण जैसे कदमों पर विचार कर सकता है.

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली लौट आयी और प्रमुख सूचकांक करीब एक प्रतिशत की गिरावट में बंद हुए. बीएसई का सेंसेक्स 702.68 अंक (0.91 प्रतिशत) गिरकर 76,847.57 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 207.95 अंक यानी 0.86 फीसदी नीचे 23,842.65 अंक पर रहा. अमेरिका और ईरान के बीच हार्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने इस महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग की घेराबंदी और अपनी शर्तों पर जहाजों को निकलने की अनुमति देने की घोषणा की है. इससे निवेशकों में ईरान युद्ध के स्थायी समाधान को लेकर निराशा बढ़ी है. मझौली और छोटी कंपनियों में भी बिकवाली का जोर देखा गया. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.77 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.46 प्रतिशत गिर गया. सभी सेक्टरों में बिकवाली हावी रही. ऑटो सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया और उसका सूचकांक दो प्रतिशत से अधिक टूट गया.

ड्रोन तकनीक में भारत-यूके का बड़ा कदम

नई दिल्ली 13 अप्रैल भारत में उन्नत एयरोस्पेस तकनीक के विकास को नई गति देते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (टीडीबी) ने 'बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक-ऑफ' परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।

जंप टेक-ऑफ तकनीक विकसित

एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूती

यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत-यूके सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कंपनी केसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटेन की एआरसी एयरोसिस्टम्स लिमिटेड के बीच साझेदारी में लागू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य हाइब्रिड प्रणोदन आधारित उन्नत टेक-ऑफ प्रणाली विकसित करना है, जो मानव रहित हवाई वाहनों और हल्के विमान प्लेटफॉर्म की परिचालन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके।

यह परियोजना विशेष रूप से 'जंप टेक-ऑफ' तकनीक पर केंद्रित है, जो पारंपरिक रनवे की आवश्यकता को कम करते हुए छोटे या सीमित स्थानों से उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करती है। प्रस्तावित प्रणाली में हाइब्रिड प्रणोदन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक ईंधन और इलेक्ट्रिक ऊर्जा दोनों का संयोजन होगा। इससे विमान को न केवल अधिक दक्षता मिलेगी, बल्कि ऊर्जा खपत भी कम होगी और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी।

> परियोजना के तहत रोटरक्राफ्ट प्रणोदन प्रणालियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए एक अत्याधुनिक टेस्ट बेंच सुविधा स्थापित की जाएगी। यह सुविधा उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली होगी और देश के एयरोस्पेस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और एयरोस्पेस डेवलपर्स को अपने उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए विश्वस्तरीय मंच उपलब्ध होगा।

सिस्टमैटिक निवेश योजना रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल घरेलू म्यूचुअल फंड उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, भले ही इक्विटी बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला हो.

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 12.2 प्रतिशत बढ़कर 73.73 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. पूरे वित्त वर्ष के दौरान निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी रही, जिससे उद्योग के एसेट बेस में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

मार्च महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों की रुचि में तेज उछाल देखने को मिला. सक्रिय रूप से प्रबंधित इक्विटी फंड्स में निवेश बढ़कर 40,450.26 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो जुलाई 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. फरवरी की तुलना में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बाजार में अस्थिरता के बावजूद निवेशकों का भरोसा बना हुआ है.

इस दौरान सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. मार्च में एसआईपी निवेश 32,087 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो फरवरी के 29,845 करोड़ रुपये से अधिक है.

हडको-एनबीसीसी एमओयू से पुनर्विकास को बढ़ावा

नई दिल्ली, 13 अप्रैल संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको औरडॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 11 अप्रैल 2026 को दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

समझौता ज्ञापनों को राधा रॉय, कार्यपालक निदेशक, हडको; भूषण कुमार, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), हडको और प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी द्वारा निष्पादित किया गया. इस अवसर पर दोनों संगठनों के प्रकार्यात्मक निदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे.

पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर एनबीसीसी के स्व-संधारणीय मॉडल की चल रही और आगामी परियोजनाओं के लिए ब्लॉक नंबर 25, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में लीजहोल्ड प्लॉट के पुनर्विकास और हडको द्वारा धन उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

इससे एनबीसीसी की स्व-संधारणीय मॉडल पर पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निधि उचित निबंधन और शर्तों पर प्राप्त की जाएगी. इससे न केवल परियोजनाओं को आरंभ करने में तेजी आएगी, बल्कि मूल्यवान सेवार्थियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन) में भी वृद्धि होगी.

उम्मीद है कि इस साझेदारी से परियोजना निष्पादन में तेजी आएगी, परिसंपत्ति मूल्य संवर्धित होगा और शहरी अवसंरचना के विकास में योगदान मिलेगा.

सोना-चांदी की कीमतों में 2 प्रतिशत तक गिरावट

नई दिल्ली, 13 अप्रैल वैश्विक बाजारों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को कीमती धातुओं—सोना और चांदी—की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी की घोषणा के बाद निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिससे सोना और चांदी दोनों में लगभग 2 प्रतिशत तक की कमजोरी देखने को मिली.

घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना वायदा करीब 0.78 प्रतिशत गिरकर 1,51,457 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 2.5 प्रतिशत टूटकर 2,37,190 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.

वैश्विक बाजार में भी दबाव देखने को मिला, जहां कॉमेक्स सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट दर्ज की गई. विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

व्यवहार प्रबंधन : पूंजी निर्माण की लुप्त हो चुकी कड़ी

निवेश करते समय जोखिम उठाने की क्षमता, समय सीमाएँ, निवेश प्रबंधक की गुणवत्ता और परिसंपत्ति आवंटन जैसे कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इनके अनुरूप ही निवेश किया जाना चाहिए, यह हम सब समझते हैं.

आशीष मालविया
प्रमुख (डिस्ट्रिब्यूशन), वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज

इन कारकों के अलावा धैर्य और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और भावनाओं के नियंत्रण की क्षमता भी उतने ही महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन्हें अक्सर कम आँका जाता है.

सही निवेश सिद्धांतों का पालन करने के बावजूद, कई बार पोर्ट्फोलियो पर उचित परिणाम दिखाई नहीं देते जिसका कारण गलत निवेश न होकर हमारा व्यवहार होता है. इसे व्यावहारिक वित्त नामक विषय के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. परंतु इस व्यवहार के कारण निवेशक जो गलती करते हैं, वो यह है कि वे दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, खासतौर पर तब, जब वह कई लोगों को संपत्ति विशेष से फायदा लेते हुए देखते हैं.

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं: मान लीजिए 2011 में एक निवेशक ने एक रियल एस्टेट संपत्ति खरीदी. उसका यह निर्णय तर्कपूर्ण था:

- उसके द्वारा ऐसी संपत्ति में पहले किए गए निवेश से उसे छः वर्षों में 2.5 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ था. उसके कई दूसरे दोस्त ऐसी ही विभिन्न संपत्तियों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे थे.
- जोखिम की प्रवृत्ति रियल एस्टेट के अनुरूप दीर्घकालिक थी.
- एक वर्ष में, संपत्ति पर प्रतिफल 30% बढ़ गया.
- दो वर्षों में, यह 50% तक बढ़ गया.

निवेशक को अपना निर्णय सभी तरह से ठीक लग रहा था और उसे इस पर गर्व भी था. हालाँकि, अगले सात वर्षों के दौरान कीमतें 50% के आसपास स्थिर रहीं. इस अवधि में, इक्विटी बाज़ार बहुत मज़बूत प्रदर्शन कर रहे थे जिससे तरलता और प्रतिफल अधिक प्रतीत हो रहे थे. इसी दौरान निवेशक को बिल्डर की ओर से देरी और कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे वह असहज हो गया. रियल एस्टेट के लिए बाज़ार में कुछ नकारात्मकता भी बढ़ी. इन सबके कारण निवेशक ने 30% के फायदे पर अपनी उस संपत्ति को बेच दिया.

कुछ वर्षों बाद, उसी संपत्ति पर 15 वर्षों की अवधि में लगभग 12 गुना का लाभ हो गया.

भारत डेटा सेंटर बाजार 2030 में होगा दोगुना

एआई निवेश और सरकारी प्रोत्साहनों से भारत बनेगा एशिया का प्रमुख डेटा हब

नई दिल्ली, 13 अप्रैल भारत का डेटा सेंटर बाजार आने वाले वर्षों में तेज गति से विस्तार करने की ओर बढ़ रहा है. वेस्टियन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र वर्ष 2030 तक दोगुना से अधिक बढ़कर लगभग 22 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि वर्ष 2025 में इसका आकार करीब 10 अरब डॉलर आंका गया है.

मजबूत डिजिटल मांग, बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता और वैश्विक कंपनियों के निवेश के चलते भारत तेजी से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में उभर रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, देश में डेटा सेंटर क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है. लगभग 30 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ भारत की क्षमता वर्ष 2026 के अंत तक 1.7 से 2.0 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 4 से 5 गीगावॉट तक हो सकती है. यह विस्तार मुख्य रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग से प्रेरित है.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी और हाइपरस्केलर कंपनियों की बढ़ती भागीदारी इस क्षेत्र के विकास को नई गति दे रही है.

समाचार विशेष

भाजपा की नई टीम पर संघ की नजर

खींची लक्ष्मण रेखा, सत्ता सुख चाहने वालों से रहें सावधान

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी की नवीन टीम के स्वरूप की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नए संगठन का ढांचा तैयार करने की कवायद पर संघ काफी सजग है.

संघ की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि नई पीढ़ी के नेता जमीन पर पसीना बहाने के बजाय केवल आभासी दुनिया की राजनीति में उलझ कर रह गए हैं. संघ की साफ हिदायत है कि संगठन में उन लोगों को कतई जगह न मिले जो विचारधारा की कीमत पर केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं.

पार्टी की कमान ऐसे हाथों में होनी चाहिए जो वैचारिक रूप से मजबूत हों और जिनका जनता से सीधा संपर्क हो. हाल के वर्षों में संघ इस बात से काफी नाराज और फिक्रमंद है कि भाजपा नेताओं का जनता से सीधा संवाद लगातार कम हो रहा है. नेता जमीन पर जाकर लोगों के बीच काम करने के बजाय संचार माध्यमों पर अपनी लोकप्रियता चमकाने का आसान रास्ता अपना रहे हैं. संघ का मानना है कि दशकों की मेहनत से बना भाजपा का सबसे मजबूत जमीनी संपर्क तंत्र इन आभासी माध्यमों के हावी होने से कमजोर पड़ रहा है.

इसलिए अहम है संघ का यह हस्तक्षेप

दरअसल नितिन नवीन के इस नए संगठन के जरिये पार्टी में एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव होने जा रहा है. यह नई पौध सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले पंद्रह से बीस वर्षों तक भाजपा की दशा और दिशा तय करेगी. आने वाले चुनावों में कई दिग्गज नेता शायद चुनावी राजनीति से किनारे हो जाएंगे. ऐसे में संघ चाहता है कि पार्टी की कमान जिन नए हाथों में जाए उनकी वैचारिक जड़ें बहुत मजबूत हों और वे सेवा, संगठन और समर्पण के मूल मंत्र पर खरे उतरें. फिलहाल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी.

क्या है राहुल की तमिल राजनीति?

नई दिल्ली. राहुल गांधी अभी तक तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं. वे बगल के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी गए और चुनावी सभा को संबोधित किया. लेकिन तमिलनाडु में कोई सभा नहीं की.

आमतौर पर दिल्ली से जाने वाले नेताओं ने एक यात्रा में दोनों जगह सभाएं की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पिछले दो महीने में तीन बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं. उन्होंने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया है. अमित शाह भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं. लेकिन तमिलनाडु में अभी कांग्रेस का इंतजार हो रहा है. कहा जा रहा है कि तीन राज्यों केरल, असम और पुडुचुरी के चुनाव के बाद ही राहुल तमिलनाडु जाएंगे. इन तीनों राज्यों में नौ अप्रैल को मतदान है.

राहुल गांधी पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के लिए गए तो उन्होंने वहां सिर्फ कांग्रेस को जिताने की अपील की. उन्होंने सहयोगियों की भी बात की लेकिन डीएमके का नाम नहीं लिया. गौरतलब है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पुडुचेरी में कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़ रही हैं. पिछली बार 14 सीट लड़ कर वह सिर्फ दो जीत पाई थी, जबकि डीएमके 13 सीट पर लड़ कर छह पर जीती थी.

एमजीआर के नाम पर चुनाव जीतने की होड़

चेन्नई. इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि अन्ना-द्रमुक के आइकॉन एमजी रामचंद्रन का नाम लेने से राजनीतिक पार्टियों को वोट हासिल होते हैं. एमजीआर के निधन के 40 वर्ष बाद भी तमिलनाडु के सियासी दलों को लगता है कि उनका नाम लेने से उन्हें चुनावी सफलता हासिल हो जाएगी.

इसलिए उनकी विरासत पर हर पार्टी अपना दावा इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कर रही है, जिसकी 234 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा और नतीजों की घोषणा 4 मई को होगी. मुख्य मुकाबला द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और अन्ना-द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन में है, जिसका हिस्सा बीजेपी भी है.

फिलहाल द्रमुक गठबंधन सत्ता में है. चूंकि एमजीआर का ताल्लुक फिल्मों से भी था, इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि तमिल सिनेमा की एक अन्य बड़ी व प्रभावी हस्ती विजय, जो टीवीके के अध्यक्ष हैं, अपनी तुलना एमजीआर से करते हैं और हर चुनावी सभा में अपने भाषण के दौरान एमजीआर का नाम लेते हैं. विजय का तो यहां तक कहना है कि जिस किस्म की आलोचना 1972 में एमजीआर की अन्ना-द्रमुक गठित करने पर हुई थी, वैसी ही आलोचना का उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है. फिल्मों में अपनी भूमिकाओं व व्यक्तिगत दान की वजह से विजय को इतनी कामयाबी अवश्य मिली थी कि लोग उन्हें 'करुण्णु एमजीआर' कहने लगे.

कमल हासन ने एमजीआर को अपना 'वाधीयार' बताया, यह दावा करते हुए कि उनकी 'परवरिश एमजीआर की गोद में हुई' और उन्होंने अपनी फरवरी 2018 की चुनावी यात्रा को एमजीआर की फिल्म 'नालाई नमाठे' के नाम पर रखा. अन्ना-द्रमुक ने अपने संस्थापक एमजीआर की विरासत को 1988 के बाद से बराबर बरकरार रखने का प्रयास किया है.

हर पार्टी कर रही विरासत का दावा

अभिनेता विजय थलापति में एमजीआर जैसे गुण नहीं हैं. उनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश या राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, जैसा कि एमजीआर की फिल्मों में था. दोनों में एकमात्र समानता यह है कि अपने फिल्मी करिअर के चरम पर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया. एमजीआर सभी जातियों, धर्मों व वर्गों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर सके, जिससे उनकी मजबूत बेस बनी. विजय अब तक यह काम नहीं कर सके हैं. वैसे यह स्वाभाविक ही है कि जो एक्टर राजनीति में प्रवेश करेगा उसकी कम से कम तमिलनाडु में तो एमजीआर से तुलना होगी ही.

विशेष | **टीएमसी-भाजपा और कांग्रेस ने सौंपी कमान**

50 सीटों पर बिहारियों का जलवा

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूं तो 294 सीटों पर सियासी मुकाबला अपने चरम पर है लेकिन करीब 50 सीमावर्ती सीटें ऐसी हैं जहां दिलचस्प 'बिहारी बनाम बिहारी' मुकाबला देखने को मिल रहा है. बिहार से सटे इन इलाकों में हिंदी भाषी मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है, जो चुनावी समीकरणों को निर्णायक बना रही है.

यही वजह है कि बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस तीनों दल इन सीटों पर खास रणनीति के तहत बिहार के नेताओं को उतारकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह बाहरी प्रभाव और पहचान की राजनीति का केंद्र बन गया है. बिहार का किशनगंज जिले की सीमा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से सटती हैं. साथ ही करीब 50 सीटें इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं. इन इलाकों में राजनीतिक दलों की सक्रियता सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है. राष्ट्रीय राजमार्ग-27 इन दिनों चुनावी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना हुआ है जहां से लगातार नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है. सड़क के दोनों ओर बंगाल का इलाका होने के कारण यह मार्ग चुनाव प्रचार का अहम गलियारा बन गया है.

हिंदी भाषी वोटरों का प्रभाव- मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे जिलों में बिहार से आए प्रवासी मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है. खासकर पासवान, यादव, कुशवाहा और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर यहां चुनावी समीकरण तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर, चाकुलिया और चोपड़ा जैसे क्षेत्र किशनगंज से सटे होने के कारण राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं.

बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत- इन सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नेताओं की पूरी फौज उतार दी है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इन इलाकों में लगातार रोड शो और रैलियां कर रहे हैं. उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल और रामसूरत राय जैसे नेता भी सक्रिय हैं.

टीएमसी और कांग्रेस की रणनीति

वहीं, टीएमसी भी पीछे नहीं है. तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है. दोनों नेता बिहारी मूल के होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी हैं, जिससे पार्टी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा तेजस्वी यादव के भी इन इलाकों में प्रचार करने की चर्चा है. कांग्रेस ने किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद को मैदान में उतारा है.